कल्पमेधा

हमे सीमित निराशा को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीमित आशा को कभी नहीं भूलना चाहिए।
- मार्टिन लूथर किंग जूनियर

विपक्ष और अवसर

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

अठारहवीं लोकसभा के चुनाव नतीजों से एक मजबूत संसदीय विपक्ष सामने आया है, जो सोलहवीं और सत्रहवीं लोकसभा में गायब था। 2014 और 2019 के पिछले दो चुनावों में, कांग्रेस क्रमशः 44 और 52 सीट के साथ मुख्य विपक्षी दल थी और वह विपक्ष के नेता का पद नहीं हासिल कर सकी थी। अन्य सभी गैर-भाजपा दल भी कम सीटें जीत पाए थे। विपक्ष की आवाज भाजपा, उसके चुनाव-पूर्व सहयोगियों और अघोषित सहयोगियों (वाईएसआरसीपी और बीजद) की संख्या और शोर में गुम हो गई थी।

भाजपा ने इस बात पर विचार करने के लिए समय नहीं निकाला कि संख्या में असंतुलन को देखते हुए, संसद की पवित्र परंपराओं को कैसे बनाए रखा जा सकता है। जैसा कि हुआ- और विपक्षी दलों ने बार-बार इसकी शिकायत की- परंपराओं का निर्वाह नहीं किया गया। कई निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के अनुसार, संसद के दोनों सदन निष्क्रिय हो गए।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित करने का अवसर दिया है। संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप ही नहीं, उसके मूल तत्त्व को भी। विपक्ष 236 सीट के साथ मजबूती से अपनी जगह पर है। विपक्ष को अरुण जेटली की इस धारणा को भूल जाना चाहिए कि सदन में बाधा डालना एक वैध संसदीय कार्य है और यह 'लोकतंत्र के हित में' होता है। वह एक कल्पना थी और सच इसके बिल्कुल उलट है।

उल्लेखनीय वादे

विपक्ष, कांग्रेस के घोषणापत्र 2024, 'न्याय पत्र' से अपनी शुरुआत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित वादे शामिल हैं:

हम वादा करते हैं कि संसद के दोनों सदन वर्ष में सौ दिन बैठेंगे और अतीत में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित और उनका ईमानदारी से पालन किया जाएगा।

हम वादा करते हैं कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्ष द्वारा सुझाए गए एजंडे पर चर्चा के लिए समर्पित होगा।

हम वादा करते हैं कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध नहीं रखेंगे, तटस्थ रहेंगे तथा उस पुरानी परंपरा का पालन करेंगे कि 'अध्यक्ष बोलते नहीं हैं'।

'इंडिया' गठबंधन इन वादों को अपनाने और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ता से लड़ने पर विचार कर सकता है।

भाजपा को सौ दिन की बैठकों, विपक्ष के एजंडे के लिए सप्ताह में एक दिन और तटस्थ पीठासीन अधिकारियों को लेकर कोई वाजिब आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

> **अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के मामले में भाजपा सबसे कमजोर है। जबकि राजकोषीय विवेक या बुनियादी ढांचे के विकास पर कोई भी विवाद नहीं हो सकता है, सभी आर्थिक नीतियों का लक्ष्य लाखों नौकरियों का सृजन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए।**

दलबदल को रोकें

नरेंद्र मोदी और, उनके कारण भाजपा अब भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से ऊपर के लक्ष्य के मुकाबले 240 सीटें हासिल करने के झटके से उबर चुकी है। उन्होंने जश्न मनाने की कोशिश की, लेकिन आम लोग जश्न मनाने के मिजाज में नहीं थे। 'अल्पमत' का ठप्पा भाजपा नेतृत्व को परेशान करेगा और वे इससे छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आकर्षक लक्ष्य वाईएसआरसीपी (4 सदस्य), आप (3), रालोद (2), जद(सेकु) (2), एजीपी (1), एजेएसयू (1), एचएएम (1) और एसकेएम (1) हैं। जद (एकी) (12) भी सुरक्षित नहीं है। इनमें से कुछ दल पहले से एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा (याद रखें कि शिवसेना के साथ क्या हुआ था)। संविधान की दसवीं अनुसूची में बहुत सारे छेद हैं, जिनमें छोटे दलों के सांसद फंस सकते हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र 2024 में एक बेहतरीन सूत्र था, जो भाजपा की योजना को विफल कर देगा :

हम संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुने गए थे, उसे छोड़ना) को विधानसभा या संसद की सदस्यता के लिए स्वतः अयोग्य घोषित करने का वादा करते हैं।

विपक्ष को दसवीं अनुसूची में संशोधन विधेयक लाना चाहिए। अगर वे संशोधन विधेयक का विरोध करते हैं, तो सत्ता पक्ष मतदाताओं की नजर में बदनाम हो जाएगा।

नौकरी के मुद्दे को आगे बढ़ाएं

अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के मामले में भाजपा सबसे कमजोर है। जबकि राजकोषीय विवेक या बुनियादी ढांचे के विकास पर कोई भी विवाद नहीं हो सकता है, सभी आर्थिक नीतियों का लक्ष्य लाखों नौकरियों का सृजन और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। भाजपा-एनडीए दोनों मामलों में विफल रही है और लोकसभा चुनावों में इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। क्या भाजपा नेतृत्व अपना रास्ता बदलेगा, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट से पता चलेगा। इस बीच, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नौकरियों से संबंधित निम्नलिखित एजंडे (कांग्रेस के घोषणापत्र 2024 से लिया गया) पर जोर देना चाहिए :

- हम एकाधिकार और अल्पाधिकार और क्रोनी पूंजीवाद के विरोधी हैं।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति वित्तीय या भौतिक संसाधनों, व्यावसायिक अवसरों या रियायतों को अकेले न हड़प ले, जो हर उद्यमी को उपलब्ध होनी चाहिए।
- हमारी नीतिगत प्राथमिकता उन व्यावसायिक उद्यमों के पक्ष में होगी, जो बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करते हैं। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग तीस लाख रिक्तियों को भरेंगे।
- नियमित गुणवत्ता वाली नौकरियों के मुकाबले अतिरिक्त भर्ती के लिए 'कर क्रेडिट' हासिल करने के मकसद से कारपोरेटों के लिए एक नई रोजगार-सन्नध प्रोत्साहन (ईएलआइ) योजना बनाएंगे।
- हम शहरी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण में शहरी गरीबों के लिए काम की गारंटी देने वाला एक शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- जल निकायों की बहाली और बंजर भूमि पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू करके कम शिक्षित, कम कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, जिसे ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।

विपक्षी दलों को ऐसे काम करने चाहिए, जैसे कि वे सरकार हों। उन्हें अवसर का लाभ उठाना चाहिए और सरकार के लिए पटकथा तैयार करना चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि बहुमत से कम वाली भाजपा नए और ऊर्जावान विपक्ष का किस तरह जवाब देती है।

किसकी जवाबदेही

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

शिक्षा में घोटालों के इस मौसम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक शानदार भाषण दिया। घोटालों का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की नई शिक्षा नीति की तारीफ की। कहा मोदीजी ने कि इस नीति का लक्ष्य है कि देश की युवा पीढ़ी के सारे सपने साकार हों। साथ में यह भी कहा कि उनका 'मिशन' है कि भारत एक बार फिर ज्ञान का केंद्र बने जैसे उस प्राचीन काल में हुआ करता था जब नालंदा में ऐसा विश्वविद्यालय था जिसका मुकाबला शायद सिर्फ तक्षशिला कर सकता था। जिस साल नालंदा को एक बर्बर मुसलिम लुटेरे ने बर्बाद किया, उस साल आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था।

सवाल यह है कि भारत ज्ञान का केंद्र कैसे बनेगा जब शिक्षा का इतना बुरा हाल है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो सकता है सिर्फ इसलिए कि शिक्षा मंत्रालय 'नीट' परीक्षा ढंग से नहीं करा पाया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले तो कहा कि कोई समस्या है ही नहीं। फिर पत्रकारों को बुलाकर स्वीकार किया कि खासी गड़बड़ी है। मगर उपाय उनका यही है कि एक जांच समिति गठित होगी जो पूरी तहकीकात करेगी। अच्छी बात है मंत्री जी, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या करेंगे जिनका भविष्य खराब हुआ है आपकी राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) की नालायकी के कारण?

कई विद्यार्थियों के डाक्टर बनने के सपने चूर-चूर हो गए हैं इसलिए कि प्रश्न-पत्र समय से पहले बाहर आ गए और परीक्षा दोबारा देने के लिए न उनकी क्षमता है न हिम्मत। कोई चौबीस लाख विद्यार्थी हैं, जिनको नई परीक्षा देनी होगी। एक बुजुर्ग ने टीवी पर कहा कि भविष्य सिर्फ विद्यार्थियों का बर्बाद नहीं हुआ है, उनके पूरे परिवारों का भी बर्बाद हुआ है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि उनको राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) पर विश्वास है तो सब कहते हैं कि उनको कोई विश्वास नहीं रहा है इस एजंसी में।

ऊपर से घोटालों की खबरें कई जगहों से आ रही हैं। पटना में एक छात्र ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसको प्रश्न-पत्र जो परीक्षा से पहले दिलवाया गया था, वह बिल्कुल वही था जो परीक्षा में आने वाला था। इस खबर को मैंने हजम ही किया था कि मालूम पड़ा कि गुजरात के गोधरा शहर में एक कोचिंग केंद्र है जहां लाखों रुपए देकर परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। घोटाले पर घोटाले सामने आए हैं पिछले दिनों जिनके बारे में लगता है कि प्रधानमंत्री को खबर नहीं मिली है, वरना वे कभी न कहते कि उनका 'मिशन' है भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने का।

> **माना कि यह समस्या मोदी के राज में नहीं पैदा हुई है। माना कि मोदी को यह विरासत में मिली है, लेकिन पिछले दस सालों में क्या किया गया है उच्च शिक्षा संस्थाओं में सुधार लाने के लिए? समस्या मेडिकल कालेजों तक सीमित नहीं है। हाल यह है कई सरकारी विश्वविद्यालयों का कि पूरी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी करने लायक नहीं होते हैं लाखों विद्यार्थी।**

लक्ष्य बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री जी, लेकिन क्या करने वाले हैं आप इन घोटालों का? क्या एनटीए में सुधार संभव हैं जब खराबी जड़ों तक पहुंच चुकी है? क्या नीट परीक्षा में किसी का भरोसा अब रहेगा, जब भ्रष्टाचार इतना दिखा है हर स्तर पर? खराबी इस हद तक है कि भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में डाक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगर युद्धग्रस्त देशों में जाने को तैयार हैं भारतीय विद्यार्थी तो केवल इसलिए कि मेडिकल कालेज भारत में इतने महंगे हैं कि विदेशों में जाना सस्ता है। सरकारी मेडिकल कालेज में दाखिला मिलना इतना मुश्किल है कि घूस देने को मजबूर हैं वे लोग जो देने की क्षमता रखते हैं।

माना कि यह समस्या मोदी के राज में नहीं पैदा हुई है। माना कि मोदी को यह विरासत में मिली है, लेकिन पिछले दस सालों में क्या किया गया है उच्च शिक्षा संस्थाओं में सुधार लाने के लिए? समस्या मेडिकल कालेजों तक सीमित नहीं है। हाल यह है कई सरकारी विश्वविद्यालयों का कि पूरी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी करने लायक नहीं होते हैं लाखों विद्यार्थी। यानी कालेज जाना बेकार होता है इतने विद्यार्थियों के लिए कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद उनके लिए रोजगार ढूंढ़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। नई शिक्षा नीति बेशक अच्छी होगी, लेकिन जब तक उच्च शिक्षा के पूरे ढांचे की मरम्मत नहीं होती है, नई नीतियों का कोई मतलब नहीं रहता है।

समस्या अब यह भी है कि शिक्षा में इन घोटालों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसद में उठाया जाएगा ये सारा मामला और मोदी सरकार को इसको लेकर घेरा जाएगा तब तक, जब तक उनके सवालों के जवाब न मिलें। क्या मोदी सरकार के पास जवाब हैं न सिर्फ विपक्ष के सवालों के, बल्कि उन तमाम विद्यार्थियों के, जिनके जीवन बर्बाद होते दिख रहे हैं? पहले समस्या थी सिर्फ चिकित्सा की पढ़ाई को लेकर, लेकिन अब लगता है कि पूरे एनटीए में इतनी खराबी आ चुकी है कि लोग मांग कर रहे हैं कि इस संस्था को बंद करके ही कोई सुधार हो सकता है। समझना मुश्किल है कि ऐसा सब कैसे हुआ है उस प्रधानमंत्री के दौर में, जिसने निजी तौर पर कई बार परीक्षा पे चर्चा की है। समझना मुश्किल है कि उनके सलाहकारों ने उनको ये कार्यक्रम कैसे बार-बार करने दिया, जब इतने सारे घोटाले छिपे हुए थे परीक्षाओं के बोझ तले।

नालंदा विश्वविद्यालय बेशक दोबारा जीवित हुआ है और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राचीन दौर से जितनी जल्दी प्रधानमंत्री वर्तमान में आते हैं, उतना उनके लिए अच्छा होगा। इसलिए कि वर्तमान में शिक्षा की समस्याएं अति-गंभीर हैं। बात सिर्फ शिक्षा संस्थाओं की नहीं है, बात है लाखों भारतीय विद्यार्थियों के भविष्य की। उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो भ्रष्टाचार नहीं महा-पाप है। उन लोगों को दंडित करना जरूरी तो है, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन उन विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारने के लिए भी कुछ करना उससे ज्यादा जरूरी है।

सबसे ऊपर लोकहित

समाज

जगमोहन सिंह राजपूत

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद से मुक्त हुए अधिकांश देशों ने शासन के लिए लोकतंत्र को अपनाया और उसके सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से व्यवस्था में लागू करने का प्रयास भी किया। मगर इसमें सभी सफल नहीं हो सके, तानाशाही, सैनिक शासन तथा चयनित व्यक्तियों का स्वार्थ इसमें आड़े आया। भारत ने जिस ढंग से लोकतंत्र का संचालन किया, उसकी विश्व में हर स्तर पर प्रशंसा हुई, और हो रही है। निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के प्रारंभिक वर्षों के नेतृत्व को दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद सत्ता उन लोगों के हाथों में आई थी, जो गांधीजी के नेतृत्व में उभरे थे, उनके दर्शन और सिद्धांतों से परिचित थे, अपने त्याग-तपस्या तथा देश-प्रेम के लिए जाने जाते थे।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाताओं का सदैव सतर्क और सजग बने रहना आवश्यक है। लोकतंत्र का व्यावहारिक स्वरूप उसके नेतृत्व की क्षमताओं से ही नहीं, उसकी अपनी आकांक्षाओं के आधार पर भी सफल या विफल साबित होता है, कई बार नए-नए अवतार लेता रहता है। भारत अनेक देशों के लिए सामान्य परिस्थितियों में अनुकरणीय उदाहरण नहीं बन सका, क्योंकि यहां लोकतंत्र की स्थापना अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुई थी। विभाजन की जो विभीषिका भारत ने झेली, वैसा विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसके अलावा यहां गरीबी, निरक्षरता, विविधिताएं, मान्यताएं और पांथिक मतभेद अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करते रहे। यह सही है कि भारत के पास एक अत्यंत परिपक्व सामूहिक नेतृत्व उपलब्ध था, जिसने गांधीजी के साथ रहकर त्याग और तपस्या के महत्त्व को न केवल समझा और स्वीकार किया था, बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार भी लिया था। उस समय के महत्त्वपूर्ण लोगों के पास संपत्ति या उसे संचय करने के किसी प्रयास की चर्चा शायद ही कभी हुई हो।

समाज में समानता, समता और सामाजिक समरसता स्थापित करने में भारतीय संविधान ने अभूतपूर्व योगदान किया है। यह अपनी गतिशीलता के लिए भी सराहा जाता रहेगा। इसमें सवा सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमे संसद भी ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती, जो इसकी मूल भावना के विपरीत हो। यह राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का ही नहीं, चयनित प्रतिनिधियों का भी उत्तरदायित्व है कि वे संविधान की मूल भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि सब इसके संरक्षण का उत्तरदायित्व निभाएं। ऐसा कर सकने में वे तभी सफल हो सकेंगे, जब उनका अपना आचरण भी संविधान-सम्मत और अनुकरणीय हो।

हर स्तर पर वैचारिक स्पष्टता, वस्तुनिष्ठता और निर्मलता बनी रहे, इसके लिए भारत में प्राचीन समय से ही अनेक व्यवस्थाएं बनाई गई थीं, जिनमें विद्वत-परिषद, सभा, संगोष्ठी, पंचायत आदि अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक दायित्वों का निर्वाह करती रहीं। ढाई हजार साल से भी पहले वैशाली और वहां के लिच्छवी गणराज्य में जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाने की व्यवस्था थी। ऋग्वेद में 'गण' शब्द का उपयोग हुआ है, जिसका अर्थ 'संख्या द्वारा शासन' यानी गणराज्य, संघ या जनतंत्र से भी है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति, उसकी आख्याओं तथा अनुभवों के आधार पर संविधान का अद्भुत आमुख बनाया, जो मनुष्यमात्र की समानता और समता को पूर्णरूपेण स्थापित करता है।

लोकतंत्र के निष्पादन में कोई व्यवधान न आए तथा उच्च वैचारिक और विश्लेषणात्मक स्तर बने रहें, इसकी विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं थीं। संसद में राज्यसभा का गठन इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को उजागर करता है कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं और समस्याओं पर संवाद का स्तर किस प्रकार ऊंचा और अनुकरणीय बना रहे। संविधान के अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति द्वारा बारह सदस्यों के नामांकन की जो व्यवस्था की गई है, वह विशेषज्ञता, अनुभव की महत्ता तथा आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाता है। ये सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, गहन अध्ययनशील तथा अपने सदाचरण से सदन की चर्चा का स्तर ऊंचा रखेंगे। जब देशहित के प्रश्न उभरेंगे, तब किसी भी दलगत लाभ की कोई अपेक्षा न रखते हुए ही सदस्य गण निर्णय ले सकेंगे। लोकहित ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है। यह सिद्धांत किसी भी स्थिति में एक भी जन-प्रतिनिधि के ध्यान से नहीं उतरना चाहिए।

> **यह राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का ही नहीं, चयनित प्रतिनिधियों का भी उत्तरदायित्व है कि वे संविधान की मूल भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि सब इसके संरक्षण का उत्तरदायित्व निभाएं। ऐसा कर सकने में वे तभी सफल हो सकेंगे, जब उनका अपना आचरण भी संविधान-सम्मत और अनुकरणीय हो।**

हर वर्तमान पीढ़ी का सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है कि वह भावी पीढ़ी को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करे। उनके सामने अपना अनुकरणीय उदाहरण रखे। आज प्रचार माध्यमों ने विधानसभा तथा संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के सीधा प्रसारण की व्यवस्था कर दी है। इसलिए किसी भी सभा में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी अपना विस्तृत प्रभाव अनगिनत लोगों पर डालती है। वहां प्रयुक्त भाषा, दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान रखते हुए अपना पक्ष रखना, शालीनता का स्तर बनाए रखना, सदन के समय के सदुपयोग का सदा ध्यान रखना तथा ऐसे ही अन्य पक्ष देशव्यापी प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। हर स्तर पर जन-प्रतिनिधि अपने व्यक्तित्व तथा आचरण से भावी पीढ़ी को सजग और सतर्क बना सकते हैं। भारत के हर नागरिक को भी समझना होगा कि लोकतंत्र ही उनके मौलिक अधिकार दिला सकता है। मगर अधिकारों को पाने के पहले कर्तव्य निभाने होते हैं।

राहुल नाम चढ़ती कला

बाखबर

सुधीश पचौरी

एंकर : संघ के बयान पर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं?
विपक्षी प्रवक्ता : अहंकार में विवेक मर जाता है?
विश्लेषक : भाजपा और संघ बंटे हैं। भाजपा में दो धड़े बने हैं- एक मोदी के साथ, दूसरा संघ के साथ।
एक प्रवक्ता : संघ अन्योन्य अलंकार है, संघ अतुलनीय है, संघ की तुलना सिर्फ संघ से ही की जा सकती है।

फिर एक दिन खबर टूटी कि अरुंधती राय द्वारा 2010 में दिए गए बयान को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा यूएपीए के अंतर्गत मुकदमा चलाने के आदेश यानी फिर 'गड़े मुर्दे उखाड़ने' की राजनीति!

इस बीच प्रधानमंत्री का जी-7 के लिए इटली दौरा, उनका पोप से झुक कर गले मिलना, विश्व के नेताओं से मिलना, साथ ही इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी द्वारा मोदी के साथ हंसते हुए एक 'सेल्फी टीजर' देकर लोगों का मनोरंजन करना।

कई चैनल चुनावों के 'मानी' खोजते रहे कि क्या एनडीए गठबंधन टिक सकता है, क्या मोदी गठबंधन सरकार चला सकते हैं। एक पक्ष कहिन कि गठबंधन टिकेगा, क्योंकि यह चुनाव पूर्व का है। नायडू अमरावती में व्यस्त रहेंगे और नीतीश अपनी 'लीगेसी' के चक्कर में रहेंगे। फिर मोदी ने आपातकाल के दिनों में 'अंडर ग्रांउड' रहकर एक ओर 'संघ भाजपा' के नेताओं और दूसरी ओर 'जमात' के नेताओं के बीच 'कोआर्डिनेशन' का काम किया! वे गठबंधन चला सकते हैं।

ऐसी बहसों में संघ के उन विशेषज्ञ की मांग बढ़ गई जो भाजपा द्वारा अपेक्षाकृत कम सीटें पाने के कारणों के बारे में लिख चुके थे।

इसी बीच एक वैश्विक 'साइबर बिल्ली' ने ईवीएम पर निशाना क्या साधा कि सारी देसी बंदूकें गरजने लगीं कि ईवीएम जाए, बैलट पेपर आए। एक कहिन कि जब इतनी बड़ी वैश्विक हस्ती ने ईवीएम को 'म्याऊं' किया है तो कुछ तो सच होगा। ईवीएम के पक्षधर बोले कि बैलट पेपर लाओ, ताकि अतीत की तरह 'बैलट लुटेरे' जीत हार तय कर सकें।

फिर आया एक चैनल पर उत्तर प्रदेश में सबसे 'लोकप्रिय कौन' वाला सर्वे, जिसने बताया कि चुनाव के बाद यूपी की जनता में राहुल की लोकप्रियता छत्तीस फीसद है, जबकि मोदी की लोकप्रियता बत्तीस फीसद है। जब यही सवाल दूसरे 'सेफालाजिस्ट' से पूछा तो जवाब मिला कि हमारा आंकड़ा ऐसा नहीं दिखाता। फिर एक दिन राहुल भाई ने 'शुक्रिया वायनाड जनता' कहा और कहा कि मेरी बहन प्रियंका वायनाड का प्रतिनिधित्व करेंगी और वे स्वयं रायबरेली सीट रखेंगे।

> **शिक्षा मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए आग बुझाने की कोशिश की कि छात्रों की चिंता सर्वोपरि, दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा, कमेटी बनाएंगे, परीक्षा पद्धति में सुधार करेंगे। बहरहाल, कल तक सरकार की लाइन लेने वाले चैनल तक सरकार के प्रति आलोचनात्मक नजर आए।**

उसके बाद भाई-बहन की जोड़ी देर तक केंद्र में रही। इसे कहते हैं राहुल नाम चढ़ती कला!

फिर भी भाजपा प्रवक्ता पहले की तरह ही 'परिवारवाद' को कोसते रहे, जबकि इस चुनाव ने परिवारवाद के आरोप को खारिज कर दिया है। शायद इसीलिए एक कांग्रेसी प्रवक्ता ने पहली बार एक चैनल पर खुलकर कहा कि हां हम हैं परिवारवादी।

फिर आया राहुल का जन्म दिन, जिसे पहली बार कई चैनलों ने देर तक जम के दिखाया। राहुल भाई चौवन बरस के हुए। एक चैनल ने लाइन दी कि राहुल 'जननायक'! एक ने कहा कि राहुल को कांग्रेस ने 'जननायक', 'पार्टी का चेहरा' बनाया जो एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वे देश की बागडोर संभालें। चुनाव के दौरान वे 'महानायक' के रूप में सामने आए हैं।

ऐसे माहौल में भी भाजपा प्रवक्ताओं के आरोप रहे कि राहुल की खटाखट वाली योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं कि वे 'तीसरी बार नाकाम' हैं। एक पत्रकार ने कहा कि राहुल को लोगों ने बधाइयां दी हैं। कार्यकर्ता आज अधिक सम्मान करते हैं... वे 'प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद' हैं जब अवसर होगा।

एक एंकर कहती दिखी कि राहुल का आत्मविश्वास बढ़ा है, अब वे पप्पू नहीं हैं। इस पर एक भाजपा प्रवक्ता कहिन कि आपने कभी इतनी तारीफ नहीं की राहुल की। एंकर ने कांग्रेस पक्षधर से सवाल किया कि अभी से जननायक कैसे बना दिया तो जवाब आया कि राहुल की यात्रा में जनता से जुड़ाव ने उनको बनाया। एंकर ने कहा राहुल 'गति अवरोधक' हैं, जिन्होंने मोदी की गति रोकी।

और फिर एक दिन 'नीट' परीक्षा में कुछ को 'ग्रेसमार्क' और फिर 'पेपरलीक' के पटना से तार जुड़े होने की खबरें। फिर सत्रह-अठारह दिन से चलता छात्र आंदोलन और फिर 'नेट' परीक्षा में पेपर लीक की खबरें। यों शिक्षा मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए आग बुझाने की कोशिश की कि छात्रों की चिंता सर्वोपरि, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कि कमेटी बनाएंगे, कि परीक्षा पद्धति में सुधार करेंगे। बहरहाल, कल तक सरकार की लाइन लेने वाले चैनल तक सरकार के प्रति आलोचनात्मक नजर आए। एक चैनल ने लाइन लगाई कि 'भारत एक 'लीक प्रधान' देश है?'

इसी बीच केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना और फिर ईडी का हाइकोर्ट जाना और जमानत पर रोक लगना, तिस पर महीने भर से दिल्ली में पानी की किल्लत, 'आप' का अनशन और विपक्ष की 'घड़ा फोड़' राजनीति।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 23 जून, 2024

दैनिक जागरण

भावनाओं पर नियंत्रण जीवन को सुगम बनाने का माध्यम है

आतंक के साथ खड़ा कनाडा

यह हतप्रभ करने वाला है कि भारत जब खालिस्तानी आतंकियों की ओर से एअर इंडिया के विमान में बम विस्फोट की 39वीं बरसी पर इस भयावह आतंकी घटना में मारे गए तीन सौ से अधिक लोगों का स्मरण कर रहा है, तब कनाडा की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच अभी जारी है। यह भारत और विश्व की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। कनाडा सरकार के इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि वह इस आतंकी घटना के लिए उत्तरदायी खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसके प्रमाण पहले भी सामने आ चुके हैं। एअर इंडिया के विमान को बम विस्फोट से ध्वस्त करने की घटना 9/11 के पहले की सबसे भीषण आतंकी वारदात थी, लेकिन कनाडा सरकार ने उसकी जांच घटना के 21 साल बाद शुरू की। चूंकि जांच का उद्देश्य दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि खालिस्तानी आतंकियों का बचाव करना था, इसलिए सिर्फ एक आतंकी को मामूली सजा दी गई और उसे भी समय से पहले रिहा कर दिया गया। जब एअर इंडिया के विमान को कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों ने निशाना बनाया था, तब वहां के प्रधानमंत्री मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। साफ है कि खालिस्तानी आतंकियों का बचाव करने के मामले में जस्टिन ट्रूडो अपने पिता से दो कदम आगे हैं। यह हाल में तब और अच्छे से प्रकट हुआ, जब फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजाब से कनाडा भागे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की बरसी पर वहां की संसद में उसे श्रद्धांजलि दी गई।

आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि बेशर्मी की पराकाष्ठा थी, क्योंकि एक समय खुद कनाडा सरकार ने उसे अपने लिए खतरा माना था और उसके बैंक खातों पर पाबंदी लगाने के साथ उसे हवाई यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। अब जब इसमें संदेह नहीं कि कनाडा सरकार खालिस्तानी आतंकियों के पक्ष में खुलकर खड़ी है और भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रही है, तब फिर भारत को उसके प्रति कठोरता का परिचय देना होगा। यह इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी सरकारी संरक्षण के चलते बेलगाम हैं। भारत को केवल कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों की सक्रियता को लेकर ही सतर्क नहीं रहना होगा। उसे ऐसी ही सतर्कता ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और अमेरिका को लेकर भी दिखानी होगी। इन देशों में खालिस्तानी चरमपंथी जिस तरह सक्रिय हैं और खुलेआम भारत को धमकी देते रहते हैं, उससे यदि कुछ पता चलता है तो यही कि ये देश भारतीय हितों के खिलाफ काम करने वाले तत्वों की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। क्या इसमें कोई संदेह है कि अमेरिका खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को संरक्षण देने में वैसी ही ढिठाई का परिचय दे रहा है, जैसे कनाडा?

स्वास्थ्य व्यवस्था

उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल ही नहीं, मेडिकल कालेज भी चिकित्सकों की भारी कमी झेल रहे हैं। तमाम दावों के बावजूद अस्पताल और मेडिकल कालेजों में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं। यहां तक कि राजधानी के दून मेडिकल कालेज को भी चिकित्सक नहीं मिल पा रहे। यहां एक ओर तमाम विभागों के चिकित्सक नौकरी छोड़ रहे हैं, वहीं रिक्त पद भरना भी अब मुश्किल हो रहा है। स्थिति यह है कि बीते दिनों दून मेडिकल कालेज में सौ से अधिक पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में महज दस चिकित्सक ही पहुंचे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कम वेतन व काम की अधिकता मुख्य वजह के रूप में उभरकर सामने आए हैं। दरअसल, सरकारी मेडिकल कालेज व अस्पतालों में एक तो चिकित्सक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद संविदा पर भरे जा रहे हैं, वहीं उनका वेतन भी काफी कम है। जबकि, निजी मेडिकल कालेज व अस्पतालों में वेतन इसका तीन से चार गुना अधिक है। इस बिंदु पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह ठीक है कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं, लेकिन इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पर्वतीय क्षेत्र में जो अस्पताल खोले गए हैं, उनमें जरूरी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। जिससे इलाज के लिए लोग शहरों का रुख करने को मजबूर हैं। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य का ढांचा तभी बेहतर हो सकता है, जब चिकित्सक व मेडिकल स्टाफ की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। चिकित्सकों को अस्पताल व मेडिकल कालेज में संविदा के बजाय स्थायी नियुक्ति मिले तो निश्चित रूप से उनके रुख में बदलाव आएगा। अस्थिरता के भाव में उनसे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी अपनी कार्यप्रणाली बदलनी होगी।

प्रश्नों के घेरे में परीक्षाएं

संजय गुप्त

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने वाले तो सशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाने के उपाय निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा यानी नीट में अनियमितता को लेकर उठे सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से कराई गई यूजीसी-नेट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आ गया। चूंकि इस परीक्षा के प्रश्नपत्र इंटरनेट मीडिया में पाए गए, इसीलिए उसे रद करना पड़ा। इसके बाद एक और परीक्षा सीएसआइआर-नेट को उसके आयोजन के पहले इसलिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ी की आशंका पाई गई। एनटीए की ओर से ही कराई जाने वाली इस परीक्षा में दो लाख छात्रों को बैठना था। यूजीसी-नेट परीक्षा में नौ लाख से अधिक छात्र बैठे थे। अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। आखिर उनके समय और संसाधन की जो बर्बादी हुई, उसकी भरपाई कैसे होगी? इस परीक्षा के प्रश्नपत्र के लीक होने की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई है, लेकिन इसके दोषी कब पकड़े जाएंगे और कब सजा दी जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। यह निराशाजनक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह तो सशक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाने वाले उपाय निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। जिस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता भंग करने वाले बेलगाम हैं, उसी तरह नकल माफिया भी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि स्कूली और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में नकल का रोग बढ़ता जा रहा है। यह ठीक है कि नई शिक्षा नीति पर अमल किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस परीक्षा नीति क्यों नहीं बन पा रही है, जिससे स्कूली परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता कायम हो सके।

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र इसलिए भी लीक होते हैं, क्योंकि उन्हें लीक कराने वालों को कठोर सजा का भय नहीं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि नीट का दोबारा आयोजन होता है या नहीं, लेकिन जब तक यह तय नहीं होता, तब तक करीब 24 लाख छात्र और उनके माता-पिता दुविधा में बने रहेंगे। पहले नीट, फिर यूजीसी-नेट और सीएसआइआर-नेट परीक्षा मामले ने एनटीए की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संस्था का गठन इसीलिए किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाएं कराने में कोई गड़बड़ी न हो पाए और परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते लाखों छात्रों को परेशानी उठानी पड़ती है तो उनका सरकार पर से भरोसा उठता है। प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं युवाओं में असंतोष उत्पन्न कर रही हैं। चूंकि ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं, इसलिए असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस असंतोष का सामना सरकारों को करना पड़ता है। समस्या यह है कि सरकारें नौकरशाही को जवाबदेह नहीं बना पा रही हैं।

अवधेश राजपूत

पिछले कुछ वर्षों से राज्यों और केंद्र की ओर से आयोजित शायद ही ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, जिसके प्रश्नपत्र लीक न हुए हों या फिर उनके परिणाम को लेकर संदेह न उठे हों। एक के बाद एक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के लीक होने पर राजनीतिक दल एक-दूसरे को कठघरे में तो खड़ा करते हैं, लेकिन इस मामले में सभी दलों और उनकी सरकारों का हाल एक जैसा है। करीब-करीब सभी राज्यों में प्रश्नपत्र लीक हो चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर कानून बना दिया है। कुछ राज्य सरकारें भी कठोर कानून बना रही हैं। ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन क्या केवल कठोर कानून प्रश्नपत्र लीक करने वालों के दुस्साहस का दमन करने में सक्षम होंगे? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि अभी तक जिन्होंने प्रश्नपत्र लीक करने-कराने का काम किया, उन्हें कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र इसलिए लीक हो रहे हैं, क्योंकि उनका आयोजन कराने वाली संस्थाएं अपना काम पुराने तरीकों से करती हैं। प्रश्नपत्र लीक होने के मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं के आयोजन में बाहरी एजेंसियों की मदद ली जा रही है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इन एजेंसियों के लोग ही पैसा कमाने के लिए धांधली करते और कराते हैं। समझना कठिन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन बाहरी एजेंसियों की मदद से क्यों कराया जाता है और वह भी ठेके पर। जब तक ठेके पर परीक्षाएं कराई जाती रहेंगी, तब तक उनकी विश्वसनीयता भंग होती रहेगी।

प्रश्नपत्र लीक होने का एक बड़ा कारण उन्हें पहले से तैयार कर छापना और फिर उन्हें विभिन्न शहरों में भेजने की परिपाटी है। कई बार इसी प्रकिया में कहीं न कहीं सेंध लग जाती है। आखिर आज के इस तकनीकी युग में पुराने तौर-तरीकों से परीक्षाएं क्यों आयोजित की जाती हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि प्रश्नपत्रों को पहले से छापने और शहर-शहर भेजने के बजाय उन्हें परीक्षा होने कुछ घंटे पहले अंतिम रूप दिया जाए और फिर उन्हें सूचना तकनीक के जरिये संबंधित केंद्रों में भेजा जाए। परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों में ही प्रश्नपत्र की प्रतियां निकालने की व्यवस्था की जाए तो परीक्षाओं में सेंध लगने से रोका जा सकता है। निःसंदेह परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर के जरिये कराई जाएं। आज जब भारत डिजिटल क्रांति का अगुआ है, तब सभी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर से क्यों नहीं हो सकतीं? आज पेन-कापी के जरिये प्रतियोगी परीक्षाएं लेने का क्या औचित्य? प्रश्न यह भी है कि प्रश्नपत्रों के कई सेट क्यों नहीं बनाए जाते, ताकि यदि कहीं कोई प्रश्नपत्र लीक भी हो जाए तो प्रदेश या देश भर में परीक्षाएं रद न करनी पड़ें।

परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने में सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आवश्यक इच्छाशक्ति का परिचय नहीं दिया जा रहा है। आखिर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं संघ लोक सेवा आयोग से कोई सीख लेने को क्यों नहीं तैयार हैं? संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष लाखों छात्रों की परीक्षा लेता है। यदि यह आयोग अपनी परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाए रखने में सक्षम है तो फिर एनटीए या इस जैसी अन्य संस्थाएं क्यों नहीं हैं? यह वह प्रश्न है, जिस पर राज्यों और केंद्र के नीति-नियंताओं को विचार करना चाहिए।

response@jagran.com

सत्ता न मिलने की खीझ ईवीएम पर

हास्य-व्यंग्य

कमल किशोर सक्सेना

खिसियानी बिल्ली भी खंभा नोचने से पहले सौ बार सोचती है, पर ईवीएम को दोष देने वाले नहीं सोचते

आज हम आपको जिस 'देवी' की कथा सुनाने जा रहे हैं, वह है तो यांत्रिक किंतु उसने बड़े-बड़े राजनीतिक तांत्रिकों के नट-बोल्ट हिला रखे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन। इसे संक्षेप में ईवीएम के लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दस साल पुराने समय को भी प्राचीनकाल कहा जाता है। यह तीव्र होते विकास और बदलाव का परिणाम है। इसी प्राचीनकाल में, भारत में चुनाव मतपत्र पर ठप्पा लगाकर उसे पेटी में डालकर होते थे। मतदान की वह प्रणाली अत्यंत सात्विक और पवित्र थी। फिर भी कुछ भ्रष्ट सरकारें चुन ली गईं। हालांकि इस पर मतभेद हैं कि सरकारें भ्रष्ट चुनी गईं या वे चुने जाने के बाद भ्रष्ट हुईं।

भ्रष्ट सरकारों से कुछ लोग इस कदर आहत हो गए कि उन्होंने संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को ही भ्रष्ट करने का बीड़ा उठा लिया, ताकि जनता भ्रमित न हो और नामांकन से शपथ ग्रहण तक पूरी चुनावी कवायद में भ्रष्टाचार की एकरूपता बनी रहे। यही वह ऐतिहासिक समय था, जब गुंडे-बदमाशों और बंदूक-बम के सहयोग से किसी दल या व्यक्ति विशेष के चुनाव चिह्न पर ठप्पा लगाने की कला का विकास हुआ। लोकतंत्र के जनक बिहार में तो मतपत्रों की लूट और मतपेटी के अपहरण जैसी घटनाओं ने धूम मचा दी। सत्ताधारियों की पौ बारह हो गई। इससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। यही काम देश के दूसरे हिस्सों और खासकर बंगाल में भी होने लगा और अभी भी होता है। वहां जब कभी मतपत्र से चुनाव होते हैं तो मतपत्र लूटे जाते हैं और मतपेटियां तालाबों, कुओं में फेंक दी जाती हैं। मतपेटियां नहीं मिलतीं तो ईवीएम को ही तोड़ने-लूटने का काम किया जाता है। ऐसे कठिन और घनघोर संकट के दौर में लोकतंत्र रूपी मंदिर को पाखंडियों से बचाने और चुनाव रूपी यज्ञ को, ईमानदारी से निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए, ईवीएम माता ने अवतार लिया। यह उसी कांग्रेस के सौजन्य से हुआ जिसे आज ईवीएम से परेशानी है।

ईवीएम से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उनकी करतूतों पर अंकुश लग गया। इससे आहत होकर उन्होंने 'माता ईवीएम' की निष्पक्षता पर ही प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए। भारत जैसे देश में यह कोई नई बात नहीं है। यहां तो त्रेता में माता सीता के चरित्र पर भी अंगुलियां उठाई गई थीं। फिर ईवीएम तो किसी खेत की मूली भी नहीं। वह ठहरी मशीनी माता, जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया। उसकी काया तार, बैटरी, लाल और हरे बटन से निर्मित होती है। कोई रग नहीं होती और न उसमें खून दौड़ता है। इसलिए इतने आरोपों के बाद भी उसका खून नहीं उबला। इसके बावजूद आरोप लगाने वालों का खून उबल गया। चुनावी शास्त्र में साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग वर्जित नहीं है। अतः विपक्ष ने इनके प्रयोग में किंचित मात्र भी संकोच नहीं किया, किंतु सत्ता रूपी सुंदरी ने उसके गले में वरमाला नहीं डाली। स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी प्रधानमंत्री का पद कई लोगों के लिए सपना ही बना हुआ है। इनमें से कुछ किसी मंडल में जाने के कगार पर हैं तो कुछ भटकते आत्मा की तरह एक से दूसरे दल में विचरण कर रहे हैं।

खिसियानी बिल्ली भी अब खंभा नोचने से पहले सौ बार सोचती है, किंतु कुंठित लोग एक बार भी नहीं। वे अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। कभी उसमें इलेक्ट्रानिक चिप लगे होने का आरोप लगता है तो कभी उसकी कमांड कहीं और होने का। ईवीएम ने हालिया चुनाव में विपक्ष को कई सीटें दिलाकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, मगर पारंपरिक भारतीय सास की तरह उन्हें ईवीएम रूपी बहू में खोट ही नजर आते हैं। मतदान के समय तो अंगुली बर्दाश्त करना उसकी ड्यूटी है, किंतु अनर्गल आरोप लगाकर बराबर अंगुली झेलना किसी के भी वश से बाहर है। ऐसे में ईवीएम का धीरज अनुकरणीय है। बोलो 'ईवीएम मैया' की जय और उस पर बुरी नजर वालों का मुंह काला।

response@jagran.com

ऊर्जा

वास्तविकता से पूर्ण जीवन

हम जो नहीं हैं, वही बनने के प्रयास में अपना ही अहित कर बैठते हैं। इसी दिखावे और ढोंग के कारण हम जीवन को जीते नहीं, बल्कि जीवन जीने का अभिनय कर रहे होते हैं। हमारे व्यक्तित्व एवं विचार और व्यवहार में सामंजस्य नहीं होने से जिंदगी बहुरूपिया बन जाती है। कितने रहस्यमयी बन जाते हैं हम कि हमें हर कदम पर एक नए पर्दे की जरूरत होती है। कोई देख न ले, कोई जान न ले, इसी उधेड़बुन में हर पल लगे रहते हैं। यही कारण है कि हम केवल चोर और अपराधियों के लिए ही घर के दरवाजे बंद नहीं रखते, अपितु अपनों के कारण भी सावधानी बरतने लगते हैं।

अपने पास जितना है उससे अधिक वाणी द्वारा प्रसारित करने के प्रयास में हमारी वास्तविकता पर ग्रहण लगता जा रहा है। स्मरण रहे कि केवल आवरण बदलने भर से आत्मा नहीं बदल जाता। जुगनू कितना भी टिमटिमाता रहे, किंतु सूर्य की जगह नहीं ले सकता। सच तो यह है कि जब हम कृत्रिमता के आवरण में लिपटा जीवन जीते हैं तब वास्तविकता प्रकट होते ही हमारी स्थिति उस भीगे हुए कागज की भांति हो जाती है, जो न लिखने लायक रहता है न जलाने लायक। जबकि व्यवस्थित और मर्यादित रहकर ही हम सात्विक, अहिंसक एवं शांतिमय जीवन के यथार्थ रस का भरपूर आनंद ले सकते हैं। केवल धर्म ही हमें ऐसे जीवन की राह दिखाने तथा इस संसार रूपी सागर में बेड़ा पार लगाने की कला सिखाता है।

हमारे लिए सर्वोत्तम स्थिति वह होगी जब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी न हो। जिस दिन हम ऐसा पारदर्शी जीवन जीने लगेंगे तब निश्चित ही परमात्मा के परम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हम जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी रहें। स्वयं अपना आकलन करें। अपनी नजरों से अपनी समीक्षा करें। कुटिल नहीं, अपितु सरल बनें। ढोंग से नहीं, बल्कि अपना जीवन इस ढंग से जिएं कि हर व्यक्ति से प्रेम, स्नेह एवं सम्मान प्राप्त कर सकें।

डा. निर्मल जैन

कोविड से अप्रभावितों का अध्ययन

मुकुल व्यास

विश्व के कुछ हिस्सों में लोग कोविड के दुष्प्रभावों से बचे रहे, जो अब भी शोध का विषय है

विश्व में कोविड के मामलों के विस्तृत अध्ययन ने विज्ञानियों को यह समझाने में मदद की है कि कुछ लोग ऐसे खतरनाक वायरस से कैसे बच गए, जिसने दुनिया में अधिकांश लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटेन में वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने असफल कोविड संक्रमण वाले लोगों की नाक के ऊतकों और रक्त में आनुवंशिक गतिविधि के विश्लेषण के आधार पर एक नए इम्यून रिस्पांस की खोज की है, जो अग्रिम पंक्ति की सुदृढ़ रक्षा प्रदान करता है। यह सही है कि वैक्सीन और उनकी बूस्टर डोज ने कोविड से मृत्यु और गंभीर जटिलताओं के जोखिम को मौलिक रूप से कम कर दिया है, लेकिन इनसे वायरस को नाक और श्वसन प्रणाली की परत में घुसने से रोकने में बहुत कम मदद मिलती है। आश्चर्य की बात यह है कि वैश्विक महामारी के बावजूद कुछ लोग पूरी तरह से कोविड-मुक्त रह गए। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुरक्षित क्यों हैं। फील्ड रिसर्च में संक्रमण के समय को सटीक रूप से निर्धारित करने में कठिनाई होती है। इस बाधा को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक चुनौती परीक्षण (चैलेंज ट्रायल) आयोजित किया, जिसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के 36 स्वस्थ प्रतिभागियों को सार्स-कोव-2 के प्री-अल्फा स्ट्रेन से जानबूझकर संक्रमित किया गया। प्रतिभागियों में से 16 को कभी टीका नहीं लगाया गया था और उनमें पहले सार्स-कोव-2 संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखे थे।

संक्रमण के बाद एक साल तक प्रतिभागियों से लिए गए रक्त और नाक से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया गया। इस असाधारण डेटासेट से टीम ने संक्रमण की तीन श्रेणियों- क्षणिक, निरंतर और निष्फल की पहचान की। शोधकर्ताओं ने टीका लगाए जाने से पहले नाक की कोशिकाओं में 'एचएलए-डीक्यूए2' जीन की भी पहचान की, जो उन कई जीनों में से एक है, जिन्हें पहले कोविड के हल्के संक्रमणों से जोड़ा गया था। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक मार्को निकोलिक का कहना है कि ये निष्कर्ष उन महत्वपूर्ण प्रारंभिक घटनाओं पर नई रोशनी डालते हैं जो या तो वायरस को पकड़ बनाने में मदद करती हैं या लक्षणों के विकसित होने से पहले इसे तेजी से खत्म कर देती हैं। उन्होंने कहा, 'अब हमारे पास विभिन्न इम्यून रिस्पांस की ज्यादा अच्छी समझ है, जो इन प्राकृतिक सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं की नकल करने वाले संभावित उपचार और टीके विकसित करने का आधार प्रदान कर सकती है। हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि मानव जीव-विज्ञान वायरस के हमले से कैसे निपटता है। हमें न केवल इस स्थायी खतरे से निपटना है, बल्कि उन और भी घातक बीमारियों से भी निपटना है जिनका हम भविष्य में सामना करेंगे।' (लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

जुड़ाव की अहम कड़ी बनी हिंदी

अधिकांश राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्रालय से कोई न कोई दुभाषिया होता है, लेकिन जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मोदी मिलते हैं तो अनुवाद की जरूरत नहीं होती। पीएम हसीना ने अपने जीवन के कुछ वर्ष दिल्ली में बिताए हैं। वह न सिर्फ हिंदी समझती हैं, बल्कि अच्छी तरह से बोल भी लेती हैं। लिहाजा मोदी और हसीना के बीच हिंदी में ही कई बार बातचीत होती है। अब इस बातचीत को भारतीय पक्ष के अधिकारी तो समझ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के तमाम अधिकारी नहीं समझ पाते। तब पीएम मोदी से हुई बात को स्वयं हसीना संक्षेप में अपने अधिकारियों को बांग्ला में बताती हैं। मोदी और हसीना के बीच हिंदी में होने वाली बातचीत को कई अधिकारी इनके बीच बढ़ते भरोसे की भी एक बड़ी वजह मानते हैं।

मंत्री पद के प्रसाद से वंचित

राजनीति के गणित भी गजब होते हैं। कई बार जीत किसी की हो, लेकिन इसका फायदा किसी अन्य को हो जाता है। केंद्र में नई सरकार के गठन में भी इसके रंग दिखाई दिए। बताया जाता है कि असम कोटे से बनने वाले मंत्रियों में सिलचर से जीते भाजपा सांसद

राजरंग

परिमल शुक्ला बैद्य का नाम लगभग तय हो गया था, मगर अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता विस्व सरमा ने अंतिम समय में बैद्य की जगह राज्यसभा सदस्य पबित्रा मार्गेरिटा के नाम की पैरवी कर दी और वह विदेश राज्यमंत्री बन गए। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई और हिमंता के बीच जारी सियासी शह-मात के खेल में बैद्य अनजाने ही शिकार हो गए। असम में गौरव को कांग्रेस के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है तो भाजपा के कर्णधार हिमंता उन्हें राजनीतिक तौर पर पछाड़ने का हर प्रयत्न कर रहे हैं। गोगोई असम के प्रभावशाली अहोम समुदाय के बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। गौरव गोगोई को जोरहाट में हराने के लिए हिमंता ने पहले तो अहोम समुदाय से ही एक दमदार प्रत्याशी तपन गोगोई को चुनावी मैदान में उतारा। फिर अपनी पूरी कैबिनेट की चुनावी ड्यूटी लगा दी और खुद भी कई दिन वहां जमे रहे। इसके बावजूद गौरव गोगोई चुनाव जीत गए। तब भी हिमंता की व्यूह रचना ढीली नहीं पड़ी। अहोम समुदाय में कांग्रेस की राजनीतिक पैठ पर ब्रेक लगाने के लिए हिमंता ने पहली बार राज्यसभा पहुंचे भाजपा नेता पबित्रा मार्गेरिटा को मंत्री पद का प्रसाद दिला दिया। पबित्रा भी अहोम समुदाय से आते हैं और उनका असली सरनेम भी गोगोई ही है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं करते। उन्होंने अपने शहर के नाम मार्गेरिटा को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। मंत्री पद की लाटरी लगने में उनके वास्तविक सरनेम गोगोई की ही अहम भूमिका रही और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी बैद्य मंत्री पद के मामले में उनसे पिछड़ गए।

खराब समय

कहते हैं कि बंद पड़ी या वक्त से पीछे चल रही घड़ी शुभ नहीं मानी जाती। इसी को लेकर भाजपा मुख्यालय के मीडिया विंग में लगी एक घड़ी चर्चा के केंद्र में है। घड़ी सही समय से आधा घंटा पीछे का वक्त बता रही थी। लोग इसे भाजपा के लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन से लेकर नई सरकार बनने के तत्काल बाद नीट परीक्षा के राष्ट्रीय मुद्दा बन जाने से भी जोड़कर देख रहे हैं। बहुमत से दूर होने के बाद भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के नेहरू के रिकार्ड की बराबरी होने के बाद मोदी सरकार नीट परीक्षा के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गई है। यहां तक कि प्रोटेम स्पीकर, जिसका काम सिर्फ नए सांसदों को शपथ दिलाने का है, उसकी नियुक्ति के मामले को भी लपककर विपक्ष ने मुद्दा बनाने का प्रयास किया। इस मामले में भी विपक्ष के हमले और उसे संविधान विरोधी और दलित विरोधी होने के नैरेटिव को देखते हुए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। संसदीय कार्यमंत्री को बचाव में उतरकर सफाई तक देनी पड़ी। ऐसा लगता है कि चुनावी मैच सरकार के लिए एक प्रकार के 'अतिरिक्त समय' में चला गया है और वह गोल बचाने के लिए रक्षात्मक मुद्रा में है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****